वित्त मंत्रालय

की

उत्पादन परिणाम निगरानी रूपरेखा

(केन्द्रीय क्षेत्र एवं केंद्र प्रयोजित ₹500 करोड़ से कम लागत वाली योजना हेतु)

OUTPUT OUTCOME MONITORING

FRAMEWORK

(For Central Sector and Centrally Sponsored Schemes costing less than ₹500 crore)

OF

MINISTRY OF FINANCE

2025-2026

विषय सूची

क्रमांक संख्या	विभाग	पृष्ठ संख्या
1.	**मांग संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग**	**1-5**
i.	भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) (सीएस)	1
ii.	भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) (सीएस)	2-4
iii.	व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) योजना	5
2.	**मांग संख्या 32 - वित्तीय सेवाएं विभाग**	**6-10**
i.	वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को भुगतान	6
ii.	प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)	7
iii.	अटल पेंशन योजना- प्रोत्साहन राशि, प्रचार अभियान	8
iv.	इंडो-स्विस सहयोग के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान	9
v.	कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति-से-व्यापारी) और प्रचार संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना	10
3.	**मांग संख्या 33 - लोक उद्यम विभाग**	**11-12**
i.	सीपीएसईज़ से संबंधित सामान्य मुद्दों पर अनुसंधान, विकास, परामर्श एंव पुनर्विन्यास।	11-12

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

वित्त वर्ष 2025-26 के संबंध में आईआईपीडीएफ हेतु ओओएमएफ

1. भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रुपए करोड़ में)	आउटपुट 2025-26			परिणाम 2025-26		
बजट अनुमान 2025-26	आउटपुट	संकेतक	वार्षिक लक्ष्य 2025-26	परिणाम	संकेतक	वार्षिक लक्ष्य 2025-26
25.00	पीपीपी मोड में, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की तैयारी के लिए तकनीकी सहायता	1.1. आईआईपीडीएफ के तहत सहायता प्राप्त नई परियोजनाओं की संख्या	12	अवसंरचना में निजी क्षेत्र की भागीदारी आमंत्रित की गई।	1.1. उन परियोजनाओं की संख्या जिनमें बोलियां आमंत्रित की गई।	06
		1.2. उन अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनमें संव्यवहार सलाहकार की नियुक्ति की गई है।	10			
		1.3. उन परियोजनाओं की संख्या जिनमें प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई है।	10			
		1.4. उन परियोजनाओं की संख्या जिनमें व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है।	8			
		1.5. उन परियोजनाओं की संख्या जिनमें डीपीआर/बोली दस्तावेज तैयार किए गए हैं।	6			
		1.6 आईआईपीडीएफ के तहत संवितरित कुल धन राशि	25 करोड़			

2. **भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) (सीएस)**

वित्तीय परिव्यय (रुपए करोड़ में)	आउटपुट 2025-26			परिणाम 2025-26		
बजट अनुमान 2025-26	**आउटपुट**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2025-26**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2025-26**
27.10	1. विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर ऋण देने में सक्षम बनाने के लिए एक्जिम बैंक को ब्याज समानीकरण सहायता (आईईएस)	1.1 एक्जिम बैंक को दिए गए ब्याज समानीकरण सहायता की राशि (करोड़ रुपये में)[1]	5059	1. भारत के कार्यनीतिक और राजनीतिक हितों में सुधार	1.1 आईईएस से एक्जिम के माध्यम से सहयता प्राप्त देशों की कुल संख्या (संचयी)	62
		1.2 विस्तारित लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) की संख्या[2]	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[3]		1.2 वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त नए देशों की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[4]
		1.3 मूल्य (अमेरिकी	लक्ष्य निर्धारित नहीं			

[1] आर्थिक कार्य विभाग के आईईएस के हिस्से के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा दिये गए अनुमान और एक्सिम बैंक का आकलन

[2] जैसा कि विदेश मंत्रालय द्वारा सलाह दी गई है (नई एलओसी के लिए, यह उधार लेने वाले देशों की मांग और भारत सरकार से अनुमोदन के अध्यधीन है)

[3] नई एलओसी के लिए उधार लेने वाले देशों और भारत सरकार से अनुमोदन के अध्यधीन

[4] यह मांग आधारित है और विदेश मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाता है

वित्तीय परिव्यय (रुपए करोड़ में)	आउटपुट 2025-26			परिणाम 2025-26		
बजट अनुमान 2025-26	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2025-26	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2025-26
		डॉलर में बढ़ाई गई एलओसी की राशि)	किए जा सकते[5]			
		1.4 विस्तारित एलओसी के तहत सहायता प्राप्त विभिन्न देशों की संख्या (संचयी)	530			
		1.5 विस्तारित एलओसी के तहत परियोजनाओं का मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	20,544	2. भारत के व्यापारिक माल और सेवा निर्यात में सुधार	2.1 वर्ष के दौरान एलओसी के माध्यम से भारत के निर्यात उत्पादों की कुल राशि (रुपए करोड़ में[6])	7085

[5] विस्तारित एलओसी पर निर्भर

[6] (आईडीईएएस दिशानिर्देशों में उल्लिखित भारत के निर्यात उत्पाद 2.2 का 75%)

	1.	1.6 आईईएस के भुगतान के लिए निधियों का उपयोग	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[7]		2.2 भारतीय निर्यातकों द्वारा अर्जित व्यापार का मूल्य (रुपये करोड़ में)	9447
		1.7 वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त नई परियोजनाओं की संख्या[8]	7		2.3 भारतीय निर्यातकों को दी गई नई संविदाओं का मूल्य (भारतीय रुपये /अमेरिकी डॉलर में)	10,172
		1.8 संविदाओं के माध्यम से लाभार्थी नए निर्यातकों की संख्या (वार्षिक आधार पर)	5	3. भागीदार देशों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार	3.1. एलओसी के तहत कार्यान्वित परियोजनाओं के माध्यम से भागीदार देशों मं सृजित नौकरियों की संख्या	14313

[7] आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा अनुमोदित बजट के अनुसार

[8] नई परियोजनाएं उधार लेने वाले देशों की मांग के अध्यधीन भी होंगी

3. व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) योजना

(रुपए करोड़ में)	आउटपुट	क्र.सं.	संकेतक	लक्ष्य 2025-26	परिणाम	क्र.सं.	संकेतक	लक्ष्य 2025-26
490.01	व्यवहार्यता अंतराल निधियन के तहत पीपीपी के माध्यम से वित्तीय/ वाणिज्यिक अवसंरचना व्यवहार्यता में सुधार करना	1.1.	उन परियोजनाओं की संख्या जिन्हें सैद्धांतिक/अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया	9	सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना में निजी क्षेत्र भागीदारी में सुधार	2.1.	अवसंरचना में कुल निजी निवेश प्रतिबद्धता	5000.00 करोड़
		1.2.	वीजीएफ योजना के तहत संवितरित निधियों की कुल राशि	490.00 करोड़				

वित्तीय सेवाएं विभाग

प्रतिफल परिणाम निगरानी फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) 2025-26 मसौदा

1. वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को भुगतान [2235.60.102.04.00.33]

वित्तीय परिव्यय (बजट अनुमान 25-26 में प्रस्तावित) (रुपए करोड़ में)	प्रतिफल 2025-26			परिणाम 2025-26		
बजट अनुमान 2025-26	**प्रतिफल**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2025-26**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2025-26**
159.20	एलआईसी को सब्सिडी का भुगतान	जारी की गई राशि	159.20*	विभेदक लाभ अर्थात् योजना के प्रबंधन के लिए किए गए व्यय के अतिरिक्त एलआईसी द्वारा अर्जित वास्तविक प्रतिलाभ और योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को सुनिश्चित प्रतिफल के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा ब्याज अंतर सब्सिडी के रूप में वहन किया जाता है।	यह योजना नए व्यवसाय के लिए दिनांक 15.8.2015 से बंद कर दी गई है। तथापि, योजना अवधि के दौरान बेची गई पॉलिसियों को उनकी पॉलिसी अवधि पूरी होने तक सेवा प्रदान किया जाना अपेक्षित होता है, इसलिए इन पालिसियों के संबंध में सब्सिडी की प्रतिपूर्ति योजना के नियमों के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को की जाती है।	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह योजना नए व्यवसाय के लिए दिनांक 15.8.2015 से बंद कर दी गई है। दिनांक 30.9.2024 की स्थिति के अनुसार, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या 3,66,847 है।

* बजट अनुमान वर्ष 2025-26 (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए) के लिए वीपीबीवाई व्यवसाय के अंतर्गत अनुमानित सब्सिडी अनुमानित निवेश प्रतिफल, अपेक्षित वार्षिकी भुगतान और अपेक्षित खर्चों पर आधारित है।

2. **प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)** [2235.60.102.04.02.33]

वित्तीय परिव्यय (बजट अनुमान 25-26 में प्रस्तावित) (रुपए करोड़ में)	प्रतिफल 2025-26			परिणाम 2025-26		
बजट अनुमान 2025-26	**प्रतिफल**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2025-26**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2025-26**
423.01	एलआईसी को सब्सिडी का भुगतान	जारी की गई राशि	423.01	विभेदक लाभ अर्थात् योजना के प्रबंधन के लिए किए गए व्यय के अतिरिक्त एलआईसी द्वारा अर्जित वास्तविक प्रतिलाभ और योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को सुनिश्चित प्रतिफल के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा ब्याज अंतर सब्सिडी के रूप में वहन किया जाता है।	यह योजना नए व्यवसाय के लिए दिनांक 1.4.2023 से बंद कर दी गई है। तथापि, योजना अवधि के दौरान बेची गई पॉलिसियों को उनकी पॉलिसी अवधि पूरी होने तक सेवा प्रदान किया जाना अपेक्षित होता है, इसलिए इन पालिसियों के संबंध में सब्सिडी की प्रतिपूर्ति योजना के नियमों के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को की जाती है।	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि योजना नए व्यवसाय के लिए दिनांक 1.4.2023 से बंद कर दी गई है। दिनांक 30.9.2024 की स्थिति के अनुसार, पीएमवीवीवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या 8,46,398 है।

* बजट अनुमान वर्ष 2025-26 (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए) के लिए पीएमवीवीवाई व्यवसाय के अंतर्गत अनुमानित सब्सिडी अनुमानित निवेश प्रतिफल, अपेक्षित वार्षिकी भुगतान और अपेक्षित खर्चों पर आधारित है।

3. **अटल पेंशन योजना- क. प्रोत्साहन राशि, ख. प्रचार अभियान** [2235.60.102.05.01.31, **और** 2235.60.102.05.02.31]

वित्तीय परिव्यय (बजट अनुमान 25-26 में प्रस्तावित) (रुपए करोड़ में)	**प्रतिफल 2025-26**			**परिणाम 2025-26**		
बजट अनुमान 2025-26	**प्रतिफल**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2025-26**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2025-26**
5.00	अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत प्रचार अभियान	प्रचार अभियानों के लिए स्वीकृत राशि	5.00	बेहतर जागरूकता से कवरेज में वृद्धि और अभिदाताओं को वृद्धावस्था सुरक्षा	नामांकित अभिदाताओं की संख्या	लक्ष्य तय नहीं किया जा सकता है क्योंकि मीडिया अभियान के कारण एपीवाई के अंतर्गत होने वाले नामांकन की गणना करना संभव नहीं है
303.00	अटल पेंशन (एपीवाई) सेवा प्रदाताओं (एसपी) को प्रोत्साहन राशि	एपीवाई एसपी को प्रोत्साहन राशि के लिए स्वीकृत राशि	303.00	नामांकन और निरंतरता में वृद्धि	नामांकित अभिदाताओं की संख्या	अटल पेंशन योजना के अंतर्गत बैंकों और डाक विभाग के लिए प्रस्तावित लक्ष्य 1.45 करोड़ है

4. इंडो-स्विस सहयोग के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान [2416.00.101.05.03.31]

वित्तीय परिव्यय (बजट अनुमान 25-26 में प्रस्तावित) (रुपए करोड़ में)	प्रतिफल 2025-26			परिणाम 2025-26		
बजट अनुमान 2025-26	**प्रतिफल**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2025-26**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2025-26**
0.80	ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि क्रियाकलापों के लिए बैंकों द्वारा ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए गैर-कृषि क्षेत्र के लिए नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त	नाबार्ड को दावों के रूप में जारी राशि	0.80	आस्ति सृजन और पूंजी निर्माण के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना	परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र ऋण के एवज में भारत सरकार द्वारा विदेशी प्रशासन को देय पुनर्भुगतान/प्रतिबद्धताओं को सुरक्षित करने के लिए विशेष निधि से नाबार्ड को पुनर्वित्त राशि जारी करना (करोड़ रुपए में)	0.80

* इंडो-स्विस सहयोग के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान प्रदान करना कोई योजना नहीं है। यह एक समझौता है।

योजना का नाम: 5) कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति-से-व्यापारी) और प्रचार संबंधी कार्यकलापों [3465.01.187.01.03.31] को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना [3465.01.187.01.02.31]

वित्तीय परिव्यय (बजट अनुमान 25-26 **में प्रस्तावित) (रुपए करोड़ में)**	**प्रतिफल** 2025-26			**परिणाम** 2025-26		
बजट अनुमान 2025-26	**प्रतिफल**	**संकेतक**	**लक्ष्य** 2025-26	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य** 2025-26
437	डिजिटल भुगतान की बढ़ती पैठ	डिजिटल भुगतान स्वीकृति अवसंरचना में वृद्धि	10%	डिजिटल भुगतान लेनदेन में वृद्धि	डिजिटल भुगतान लेनदेन की संख्या में प्रतिशत वृद्धि (वित्तीय वर्ष 2024-25 से % वृद्धि)	25%
		भीम-यूपीआई लेनदेन में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)	30%			
		भीम-यूपीआई के माध्यम से मर्चेंट डिजिटल भुगतान लेनदेन (पी2एम) की संख्या (करोड़ में)	15,000			
		यूपीआई लाइट सेवाएं प्रदान करने वाले बैंकों की संख्या	50			
		यूपीआई 123पे सेवाएं प्रदान करने वाले बैंकों की संख्या	15			

नोट : चूंकि रुपे डेबिट कार्ड प्रोत्साहन योजना प्रस्ताव का हिस्सा नहीं है, इसलिए प्रोत्साहन योजना के ओओएमएफ से रुपे डेबिट कार्ड से संबंधित मापदंडों को हटा दिया गया है।

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) संकेतकों के लिए युक्तिकरण

स्कीम का नाम: अनुसंधान, विकास, परामर्श एवं पुनर्विन्यास* (आरडीसीआर)*

वित्तीय परिव्यय (रुपए करोड़ में)	आउटपुट 2025-26			आउटकम 2025-26		
बजट अनुमान 2025-26	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य	आउटकम	संकेतक	लक्ष्य
8.38	1. सीपीएसई और एसएलपीई से संबंधित सामान्य मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन, प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित करना	1.1 किए गए अनुसंधान/विषयगत अध्ययनों की संख्या	2	1. सीपीएसई और एसएलपीई के लिए सामान्य मुद्दों पर अनुसंधान, अध्ययन, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का उपयोग करना	1.1 विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत शामिल सीपीएसई की संख्या	50
		1.2 सीपीएसई के लिए कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के प्रशिक्षण सहित सीपीएसई/एसएलपीई के कार्यपालकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	19		1.2 एवं 1.3 विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत शामिल किए गए सीपीएसई की संख्या तथा भाग लेने वाले/प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	50 सीपीएसई/एसएलपीई और 500 प्रतिभागी
		1.3 सीपीएसई के कार्यपालकों/निदेशकों के लिए आयोजित कार्यशालाओं/ अभिमुखीकरण कार्यक्रमों की संख्या	18			50 सीपीएसई/एसएलपीई और 500 प्रतिभागी

वित्तीय परिव्यय (रुपए करोड़ में)	आउटपुट 2025-26			आउटकम 2025-26		
बजट अनुमान 2025-26	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य	आउटकम	संकेतक	लक्ष्य
		1.4 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग प्रक्रियाओं की संख्या।	1		1.4 विभिन्न कार्यकलापों के तहत शामिल किए गए सीपीएसई (महारत्न और नवरत्न) की संख्या	38 चुनिंदा रत्न सीपीएसई
		1.5 अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए पुरस्कार या प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले सीपीएसई की संख्या	5	2. दक्षता, लाभप्रदता और मानव संसाधन प्रथाओं के संदर्भ में निष्पादन में सुधार	1.5 विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत शामिल किए गए सीपीएसई की संख्या	50 सीपीएसई
		1.6 वीआरएस/वीएसएस का विकल्प चुनने वाले या उनके पात्र आश्रितों के लिए आयोजित प्रशिक्षण/पुनर्विन्यास कार्यक्रमों की संख्या।	लागू नहीं**			

*- *2025-26: आरडीसी और सीआरआर स्कीमों का विलय कर दिया गया था, और अब लोक उद्यम विभाग द्वारा केवल एक स्कीम संचालित है, जिसका नाम आरडीसीआर स्कीम है।*

**- *आरडीसीआर स्कीम में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का प्रावधान नहीं है। चूंकि इस स्कीम के अंतर्गत मांग अथवा उपाय यदा-कदा उत्पन्न होती है या किया जाता है, इसलिए कोई मापनीय मानदंड नहीं हो सकता। इसलिए, इसे 'लागू नहीं' के रूप में माना जा सकता है।*

INDEX

Sl. No.	Departments	Page no.
1.	**Demand No. 30- Department of Economics Affairs**	**15-18**
i.	India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) (CS)	15
ii.	Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS)(CS)	16-17
iii.	Viability Gap Funding (VGF) Scheme	18
2.	**Demand No. 32-Department of Financials Services**	**19-23**
i.	Payment to LIC for Pension Plan for Senior Citizens	19
ii.	Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)	20
iii.	Atal Pension Yojana-Incentive, Promotional Campaign, Gap Fund	21
iv.	Grants to NABARD to settle claims under Indo-Swiss Cooperation	22
v.	Incentive scheme for promotion of low-value BHIM-UPI transactions (person-to-merchant) and Promotional Activities	23
3.	**Demand No.33 - Department of Public Enterprises**	**24**
i.	Research Development, Consultancy & Reorientation (RDCR) on Generic issue related to CPSEs.	24

Ministry of Finance

Department of Economic Affairs

OOMF for IIPDF pertaining to Financial Year 2025-26

1. India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) (CS)

FINANCIAL OUTLAY (Rs in Cr)	**OUTPUTS 2025-26**			**OUTCOMES 2025-26**		
2025-26	**Output**	**Indicators**	**Annual Target 2025-26**	**Outcome**	**Indicators**	**Annual Target 2025-26**
25.00	Technical Support for preparing quality infrastructure projects, in PPP mode	1.1. No. of new projects supported under IIPDF	12	Inviting Private Sector participation in infrastructure	1.1. No. of projects in which bids are floated.	06
		1.2 No of approved projects in which TA is appointed	10			
		1.3 No of projects in which Inception Report is prepared	10			
		1.4 No of projects in which Feasibility Report is prepared	8			
		1.5 No of projects in which DPR/ bid documents are prepared	6			
		1.6 Total amount of funds disbursed under IIPDF	25 cr.			

2. Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS)(CS)

FINANCIAL OUTLAY (Rs in Cr)	OUTPUTS 2025-26			OUTCOMES 2025-26		
2025-26	**Output**	**Indicators**	**Targets 2025-26**	**Outcome**	**Indicators**	**Target 2025-26**
27.10	1. Interest Equalization Support (IES) to the EXIM Bank to enable it to lend to developing nations on concessional terms	1.1. Amount of interest equalization support given to EXIM Bank (in Rs Crore)[1]	5059	1. Improved strategic and political interests of India	1.1 Total No of countries supported through IES to EXIM (cumulative)	62
		1.2. No. of Lines of credit (LOCs) extended[2]	Target not amenable.		1.2 Number of new countries supported during the year	Target not[4] amenable.
		1.3. Value (amount of LOCs extended in USD) (Data dependent on Item 1.2	Target not[3] amenable.			
		1.4. No. of projects supported under LOCs extended to different countries (Cumulative)	530			

[1] *Estimate provided by MEA and Exim Bank projection for DEA portion of IES*

[2] *As advised by MEA.(* For new LoCs, it is subject to demand from borrowing countries and approval from GOI)

[3] For New LOCs, it subject to demand from borrowing countries and approval from GoI.

[4] This is demand-driven and decided by MEA.

FINANCIAL OUTLAY (Rs in Cr)	OUTPUTS 2025-26			OUTCOMES 2025-26		
2025-26	**Output**	**Indicators**	**Targets 2025-26**	**Outcome**	**Indicators**	**Target 2025-26**
		1.5. Worth of projects under LOC extended (in USD Mn)	20,544	2. Improved India's merchandise and service's export	2.1 Total amount of India's export products through LOCs during the year (in Rs Crores[5])	7085 Cr.
		1.6. Utilization of funds towards payment of IES	Target not amenable[6].		2.2 Value of business accrued to Indian exporters (in Rs Crores)	9447
		1.7. No. of new projects supported during the year[7]	7		2.3 Value of new contracts awarded to Indian exporters (in INR/USD)	10,172
		1.8. No of new exporters benefited through contracts (on Annual Basis)	5	3. Improved socio-economic status of partner countries	3.1. Number of jobs Created in partner country through projects implemented under LOC	14313

[5](75% of 2.2 India's export products as mentioned in IDEAS guidelines)

[6]As per the budget approved by Department of Economic Affairs.

[7](New Projects will also be subject to demand from borrowing countries

3. Viability Gap Funding (VGF) Scheme

BE	1. Output				2. Outcome			
(In Rs. Cr)	**Output**	**S.No.**	**Indicator**	**Target 2025-26**	**Outcome**	**S.No.**	**Indicator**	**Target 2025-26**
490.01	Improve financial/commercial viability of infrastructure projects through PPP under Viability Gap Funding	1.1.	No. of projects granted In-Principle/Final Approval.	9	Improved Private Sector participation in Social and Economic Infrastructure	2.1.	Total private investment committed in infrastructure	5000.00 Cr.
		1.2.	Total amount of funds disbursed under the VGF Scheme	490.00 Cr.				

Ministry of Finance

Department of Financial Services

Draft Output Outcome Monitoring Framework (OOMF) 2025-26

1**. Payment to LIC for Pension Plan for Senior Citizens [2235.60.102.04.00.33]**

Financial Outlay (Proposed in BE 25-26) (Rs.in Cr)	**OUTPUTS 2025-26**			**OUTCOMES 2025-26**		
BE 2025-26	**Output**	**Indicators**	**Targets 2025-26**	**Outcome**	**Indicators**	**Target 2025-26**
159.20	Payment of subsidy to LIC	Amount released	159.20*	The differential return, i.e., the difference between actual return generated by LIC and the assured return to senior citizens under the scheme in addition to expenses incurred for managing the scheme are borne by Government of India as interest-gap subsidy.	The scheme is discontinued w.e.f. 15.8.2015 for new business. However, policies sold during the currency of scheme period are required to be serviced till the completion of their policy period, as such, subsidy in respect of these policies is reimbursed to LIC of India in terms of rules of the scheme.	No targets can be fixed as the scheme is discontinued w.e.f. 15.8.2015 for new business. As on 30.9.2024, total number of beneficiaries under the Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY) are 3,66,847.

* *The estimated subsidy under VPBY business for the year BE 2025-26 (For F.Y. 2024-25) are based on the projected investment yields, expected annuity payments and expected expenses.*

2. Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) [2235.60.102.04.02.33]

Financial Outlay (Proposed in BE 25-26) (Rs.in Cr)	OUTPUTS 2025-26			OUTCOMES 2025-26		
BE 2025-26	**Output**	**Indicators**	**Targets 2025-26**	**Outcome**	**Indicators**	**Target 2025-26**
423.01	Payment of subsidy to LIC	Amount released	423.01	The differential return, i.e., the difference between actual return generated by LIC and the assured return to senior citizens under the scheme in addition to expenses incurred for managing the scheme are borne by Government of India as interest-gap subsidy.	The scheme is discontinued w.e.f. 1.4.2023 for new business. However, policies sold during the currency of scheme period are required to be serviced till the completion of their policy period, as such, subsidy in respect of these policies is reimbursed to LIC of India in terms of rules of the scheme.	No targets can be fixed as the scheme is discontinued w.e.f. 1.4.2023 for new business. As on 30.9.2024, total number of beneficiaries under the PMVVY are 8,46,398.

* *The estimated subsidy under PMVVY business for the year BE 2025-26 (For F.Y. 2024-25) are based on the projected investment yields, expected annuity payments and expected expenses.*

3. Atal Pension Yojana- a. Incentive, b. Promotional Campaign, [2235.60.102.05.01.31 and 2235.60.102.05.02.31]

Financial Outlay (Proposed in BE 25-26) (Rs.in Cr)	Outputs 2025-26			Outcomes 2025-26		
BE 2025-26	**Output**	**Indicators**	**Targets 2025-26**	**Outcome**	**Indicators**	**Target 2025-26**
5.00	Promotional Campaign under Atal Pension Yojana (APY)	Amount sanctioned for Promotional campaigns	5.00	Better awareness leading to more coverage and old age security to the subscribers	Number of subscribers enrolled	Target not amenable as it is not possible to calculate the enrolments that would happen under APY due to media campaign
303.00	Incentive to Atal Pension (APY) Service Providers (SPs)	Amount Sanctioned for Incentive to APY SPs	303.00	Increases enrolments and persistency	Number of subscribers enrolled	Proposed target to Banks and D/o Post under APY is 1.45 crore

4. Grants to NABARD to settle claims under Indo-Swiss Cooperation [2416.00.101.05.03.31]

Financial Outlay (Proposed in BE 25-26) (Rs.in Cr)	OUTPUTS 2025-26			OUTCOMES 2025-26		
BE 2025-26	**Output**	**Indicators**	**Targets 2025-26**	**Outcome**	**Indicators**	**Target 2025-26**
0.80	Refinance by NABARD for non-farm sector to increase the flow of credit by banks for non-farm activities in rural areas	Amount released as claims to NABARD	0.80	Promotion of non-farm sector, through asset creation and capital formation	Release of refinance amount to NABARD from a Special Fund to cover repayments/ commitments due from GoI to the foreign administration against the Rural Non-Farm Sector credit under the project (in Rs. Cr)	0.80

* *Grants to NABARD to settle claims under Indo-Swiss Cooperation is not a Scheme. It is an agreement.*

5. Incentive scheme for promotion of low-value BHIM-UPI transactions (person-to-merchant) [3465.01.187.01.02.31] and Promotional Activities [3465.01.187.01.03.31]

Financial Outlay (Proposed in BE 25-26) (Rs.in Cr)	OUTPUTS 2025-26			OUTCOMES 2025-26		
BE 2025-26	**Output**	**Indicators**	**Targets 2025-26**	**Outcome**	**Indicators**	**Target 2025-26**
437	Increased penetration of Digital Payments	Increase in Digital Payment acceptance infrastructure	10%	Growth of Digital Payment transactions	Percentage increase in the number of Digital Payment Transactions (% increase from FY 2024-25)	25%
		YoY growth in BHIMUPI transactions (%)	30%			
		Number of merchant Digital Payment transactions (P2M) via BHIM-UPI (in crore)	15,000			
		Number of banks offering UPI Lite Services	50			
		Number of banks offering UPI 123PAY Services	15			

Note: As RuPay Debit Card is not part of the incentive scheme proposal, parameters related to RuPay Debit Card have been removed from the OOMF of the Incentive scheme.

Ministry of Finance

Department of Public Enterprises

Rationalization for OOMF indicators for the FY 2025-26

Name of the Scheme: Research, Development, Consultancy and Reorientation* (RDCR)*

Financial Outlay (Rs in Cr)	**Output 2025-26**			**Outcomes 2025-26**		
BE (2025-26)	**Output**	**Indicators**	**Target**	**Outcome**	**Indicators**	**Target**
8.38	1.To undertake Research Studies, Training, Seminars, Workshops on Generic Issues related to CPSEs and SLPEs	1.1 No. of Research/Thematic Studies undertaken	2	1. Utilization of Research Studies, Training and Workshops on Generic issues to CPSEs and SLPEs	1.1 No. of CPSEs covered under various activities	50
		1.2 No. of Training Programs for Executives of CPSEs / SLPEs conducted including training on performance appraisal system for CPSEs.	19		1.2 & 1.3 Number of CPSEs covered under various activities and No. of persons participated/trained	50 CPSEs/SLPEs and 500 participants
		1.3 No. of Workshops/ orientation programs for Executives/ Directors of CPSEs held	18			50 CPSEs/SLPEs and 500 participants
		1.4 No. of collaborations with national & international organizations done.	1		1.4 Number of CPSEs (Maharatna & Navratna) covered under various activities	38 Select Ratna CPSEs
		1.5 No. of CPSEs granted award or incentive for their best practices.	5	2. Improvement in performance in terms of efficiency, profitability and HR Practices	2.5 Number of CPSEs covered under various activities	50 CPSEs
		1.6 No. of training/reorientation programs organized for VRS/VSS optees or their eligible dependents.	Not Applicable**			

**- 2025-26: The RDC & CRR schemes were merged, and now the DPE operates only one Scheme, namely the RDCR Scheme.*

***- The RDCR Scheme does not provide for the organization of such programmes. Since the demand or intervention under this scheme is sporadic, there cannot be any measurable parameters. Therefore, this may be treated as 'Not applicable'.*